

के लिए अधिकतम सीमा तक इस मात्रा में वृद्धि करने के लिए व्यवहार्यता की जांच कर सकता है।

Reduction in Diesel Price For Small Fishing Boats

176. SHRI K. B. CHOUDHARI :
PROF. P. J. KURIEN :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to reduce the diesel price for small fishing boats by exempting Central excise duty as has been done in the case of deep sea fishing trawlers; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) The scope of exemption presently admissible to fishing trawlers including deep sea fishing vessels is being maintained for the time being at the same level.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के बारे में वास्तविकता जानने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट

*177. श्रीमती किशोरी सिन्हा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तविकता जानने के लिए बनायी गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान अति दयनीय और कमजोर है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति ने 180 योजनाओं में से 26 योजनाओं का निरीक्षण किया और 13 योजनाओं में कार्य की कोटि को अपेक्षाकृत घटिया पाया। समिति द्वारा बनायी गयी सामान्य त्रुटियाँ चिनाई तथा सीमेंट कंक्रीट की घटिया कोटि असन्तोषजनक गारा मिश्रण, खारे पानी का प्रयोग तथा अपर्याप्त स्थल निरीक्षणों से संबन्धित थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुव्यवस्थित सर्वेक्षण तथा त्रुटियों को सुधारने, सुदृढीकरण उपायों का कार्यान्वयन, निरीक्षण पद्धति को सरल बनाने, सख्त पर्यवेक्षी अनुशासन को सुनिश्चित करने कार्य स्थल पर सामग्रियों की जांच से संबन्धित उचित रजिस्टर रखने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, दोषी ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने आदि के लिये कार्यवाही की है।

Restriction on Purchase of Rice from Surplus States

*178. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR :
SHRI SKARIAH THOMAS :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether there is any restriction on Government agencies of any State for purchasing rice from other surplus states ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government of Kerala have requested Union Government for full freedom to the Kerala State Civil Supplies Corporation to purchase rice from open market in the surplus States ; and

(d) if so, the details of the request and the action by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) The whole country is treated as single zone for inter-State movement of rice through normal channels. Levy free rice can be moved freely within the country by the traders. The State Government or their agencies are, however, required to obtain prior approval of the General Govern-

ment for inter State movement of levy free rice on State Government account.

(c) and (d) Central Government have received requests from time to time from the Government of Kerala to allow them to purchase 30,000 to one lakh tonnes of levy free rice from the surplus States. Taking into account availability in the surplus States, Kerala Government were allowed to purchase during 1982-83 Kharif marketing season, 75,000 tonnes of rice in all, 15,000 tonnes from Punjab/Haryana, and 60,000 tonnes from Andhra Pradesh.

Increase In Pure Ghee Prices

*179. SHRI MOHANLAL PATEL :
SHRI CHINTAMANI JENA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pure ghee prices are shooting up day by day not only in private sector but in public sector also;

(b) if so, the reasons for the increase in pure ghee prices throughout the country; and

(c) the steps being taken to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) There has been some increase in the prices of Desi Ghee both in private and public sectors.

(b) The production and marketing of Desi Ghee is largely in the hands of private-sector Desi ghee is also not subject to any price control. Increase in prices of desi ghee appears to have been influenced by the behaviour of the prices of edible oils, feed, fodder and milk and prices of other essential commodities.

(c) Government has consistently undertaken a number of programmes in the Central sector and State Plans for development of livestock and dairies for increasing production of milk and to maintain the price of milk and milk products at reasonable levels keeping the interest of producers and consumers in view.

सुरत, गुजरात में कमान्ड एरिया
डेवलपमेंट के लिए सहायता

*180. श्री छोटू भाई गामित : क्या सिंचाई

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उकाई काकाडापुर कमान्ड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, सुरत, गुजरात ने भारत सरकार से कमान्ड एरिया के विकास की योजना में सहायता करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजना के लिए कुल कितनी राशि की सहायता की मांग की गई है और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) गुजरात सरकार के अनुरोध पर उकई ककरापार परियोजना 1974 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थापना, सर्वेक्षणों, फील्ड चैनलों का निर्माण करने, भूमि समतल करने, फील्ड ड्रेनों का निर्माण करने तथा वारंबंदी लागू करने जैसी आइटमों पर हुए व्यय के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को बराबर की सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार से कार्यक्रम में सम्मिलित सभी परियोजनाओं के लिए दावे प्राप्त होते हैं न कि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग। गुजरात सरकार ने वर्ष 1983-84 के लिए 256.22 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में दी गई है, पहली किस्त पिछले वर्ष में व्यय न की गई शेष राशि को समायोजित करते हुए एक वर्ष में देय राशि की लगभग आधी थी। 1982-83 में गुजरात सरकार को दी गई कुल राशि में से व्यय न की गई 30.07 लाख रु० की शेष राशि को हिसाब में लेते हुए, 102.55 लाख रुपए की राशि दी गई है। जनवरी, 1984 तक वास्तविक कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष